आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 19.11.2025 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 9 करोड़ किसानों को 18 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की पीएम–किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दोनों मंडलों में एक–एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
- केंद्र ने उत्तराखंड को खनन के क्षेत्रों मे सुधार कार्यों पर फिर से दी 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। खनन सुधार में राज्य पहले स्थान पर।
- शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगाया।

प्रधानमंत्री / किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में देशभर के नौ करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 18 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की पीएम–किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने आज कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी की उर्वरता और फसलों के पोषण को बहाल करने के लिए प्राकृतिक खेती के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दोनों मंडलों में एक–एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। आज ''मुख्यमंत्री आवास'' में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री धामी ने कहा कि इस परियोजना के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ ही तीर्थ स्थलों व उनके आस–पास के क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाना है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को इसी वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कार्य धरातल पर शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय हस्तशिल्प, पर्वतीय उत्पादों और सांस्कृतिक आयोजनों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य का पर्यटन परिदृश्य और समृद्ध होगा तथा उत्तराखंड की पहचान 'आध्यात्मिक राजधानी' के रूप में और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में शीतकालीन यात्रा

व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की शीतकालीन स्थलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करते हुए, वहां की यात्रा, आवास, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कर सकें।

वाइब्रेंट विलेज

केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश में चीन और नेपाल सीमा से सटे 91 गांवों का चयन किया गया है। इनमें चीन सीमा से सटे 51 गांव और नेपाल सीमा के 40 गांव शामिल हैं। योजना का उद्देश्य इन दुर्गम सीमांत गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर वहां के नागरिकों को बेहतर जीवन–स्तर, सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आज देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेशी जोशी ने ग्राम्य विकास आयुक्त से वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रगति रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्राप्त की। श्री जोशी ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, व्यापक प्रचार–प्रसार और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश देते हुए सीमांत गांवों के समग्र विकास पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आजीविका सृजन और आबादी को रोकने के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य के 91 गांवों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना, प्रदेश के दूरस्थ गांवों में आधुनिक सुविधाएं, स्थायी आजीविका, कृषि–बागवानी, सुरक्षित वातावरण और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

प्रोत्साहन राशि

केंद्रीय ख़ान मंत्रालय ने वर्ष 2025–26 की विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इससे पहले भी गत अक्टूबर माह में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। राज्य ने हाल के वर्षों में खनन सुधारों पर जोर देते हुए बेहतर नीतियां लागू करने के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र द्वारा बताया गया है कि राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक कार्यवाहियों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है। खासतौर पर माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित सात में से छह प्रमुख सुधारों के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने वित्त मंत्रालय से राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई– निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिसके सकारात्म परिणाम नजर आने लगे हैं।

हड़ताल प्रतिबंध

उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से आगामी छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।

पंचायत चुनाव मतदान

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर कल मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 27 हजार से अधिक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया कि 340 पदों पर होने वाले मतदान के लिए 254 बूथ बनाए गए हैं।

इको सेंसेटिव जोन

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में भागीरथी इको सेंसेटिव जोन निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि इको सेंसेटिव जोन की परिधि में तत्काल सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग, संबंधित विभागों और एजेंसियों को नदी से सटे क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और अन्य सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने गैर कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति के बारे में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान, पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े विभिन्न प्रावधानों का व्यापक अध्ययन करने के निर्देश दिए।